

पर्यावरणीय सूचकांक पर भारत का कमज़ोर प्रदर्शन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत को 180 देशों की सूची में 177वाँ स्थान दिया गया है। जबकि वर्ष 2016 के पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक में भारत 141वें स्थान पर था।

पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक (Environmental Performance Index- EPI)

- इस रिपोर्ट को हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के सम्मलेन में जारी किया गया है।
- यह एक द्विवार्षिक (biennial) रिपोर्ट है। 24 प्रदर्शन संकेतकों पर आधारित EPI को विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है।
- इस सूची में समकक्ष उभरती अर्थव्यवस्थाओं, ब्राज़ील और चीन को क्रमशः 69वें और 120वें स्थान पर रखा गया है।

पर्यावरण संरक्षण के लिये सरकार द्वारा किये गए हालिया नीतित्त्वित प्रयास

- कोयला-आधारित ऊर्जा संयंत्रों के लिये दिसंबर 2015 में अधिसूचिति सख्त और नवीन पर्यावरणीय मानकों को जनवरी 2018 से लागू करना।
- 1 अप्रैल, 2020 से भारत स्टेज-5 (BS-V) को छोड़ते हुए सीधे भारत स्टेज-6 (BS-VI) उत्सर्जन मानकों को लागू करने का नरिणय।
- 2030 तक देश में वदियुत वाहनों के उत्पादन और बकिरी के लिये एक रूपरेखा नरिमाणधीन।
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण को तीव्र करने के लिये राष्ट्रीय सौर मशिन के तहत 2021-22 तक 20 गीगावाट की सौर क्षमता स्थापति करने के लक्ष्य को संशोधित करते हुए इसे 100 गीगावाट करना।
- इसके अतरिकित केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया है कि उच्च प्रदूषित गंगा नदी को 2018 तक पूरुणतया साफ कर दिया जाएगा।

प्रयासों के बावजूद कमज़ोर प्रदर्शन का कारण

- हालाँकि सौर क्षमता संबंधी लक्ष्यों के मामलें में प्रगति हुई है कति कई अन्य लक्ष्यों में विशेष प्रगति नहीं हुई है। नीतित्त्वित लक्ष्यों और कार्रवाई के बीच एक बड़ा अंतर दिखाई देता है।
- सरकार द्वारा दिसंबर 2017 तक सख्त ऊर्जा-संयंत्र उत्सर्जन मानकों को लागू करने में ढलाई बरती जा रही है और ऐसी चर्चा है कि इन मानकों को शथिलि भी किया जा सकता है।
- ऑटोमोबाइल औद्योगिकि समूहों ने भी यह स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्तमान अनुमानों के आधार पर इलेक्ट्रिकि वाहनों की ओर पूरुण स्थानांतरण वास्तविकि रूप से 2047 तक ही संभव हो सकेगा।
- इलेक्ट्रॉनिकिस वनिरिमाताओं के स्थापति हो जाने के बाद बाज़ार में बेचे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिकि उत्पादों के अपशषित संग्रहण के वार्षिकि लक्ष्य को 30% से घटाकर 10% तक कम कर दिया गया है।
- पछिले वर्ष नरियंत्रक और महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट में गंगा नदी को साफ करने के लिये आवंटित धन का सही तरीके से उपयोग नहीं करने और कार्ययोजना वकिसति नहीं करने पर सरकारी कार्यवाही पर नकारात्मक टपिपणी की गई थी।
- हालाँकि यह अव्यवस्था केवल हालिया नीतित्त्वित वफिलताओं का परिणाम नहीं है। यह मौजूदा पर्यावरण कानूनों और वनियिमों को लागू करने में प्रशासनिकि इच्छाशक्ति की कमी से भी जुड़ा हुआ है।

पर्यावरणीय नमिनीकरण की लागत पर वकिस के दुष्परणाम

- विश्व बैंक और इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिकिस एंड इवैल्यूएशन (वाशिंगटन विश्वविद्यालय, U.S.A.) के एक हालिया अध्ययन के मुताबकि भारत में अनुमानित 1.4 मिलियन समय से पहले मौतों (Premature Deaths) की एक प्रमुख वजह वायु प्रदूषण है।
- इसके कारण कलयाणकारी गतविधियिों में भारत का 2013 में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 8% के बराबर नुकसान हुआ है। श्रम उत्पादकता की लागत में 0.84% तक का नुकसान हुआ।
- पर्यावरणीय नमिनीकरण के कारण गरीबों का आनुपातिकि रूप से अधिक प्रभावित होना चतिता का वषिय है। इसके अलावा, कई अन्य प्रमुख पारस्थितिकि प्रभावों के वैज्ञानिकि समझ की कमी के कारण पर्यावरणीय नमिनीकरण के अन्य रूपों का आकलन नहीं किया जा सका है।

आगे की राह

- पर्यावरणीय समस्याओं का वास्तविक समाधान विकास की पर्यावरणीय लागतों को पहचानने और इन लागतों को तार्किक बनाने में है।
- सौर ऊर्जा की ओर तीव्र संक्रमण के लिये सब्सिडी देने के साथ ही अधिक प्रदूषणकारी ईंधनों, जैसे-पेट्रोल और डीजल की कीमत के उचित निर्धारण से भी इसे पूरति किया जा सकता है।
- कोयला-आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली की लागत, आंशिक रूप से ही सही उपभोक्ताओं से वसूली जाने वाली कीमत में प्रतबिंबित होनी चाहिये।
- इसी तरह, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की ओर संक्रमण में इन वाहनों के मूल्य निर्धारण में इनकी सामाजिक लागत का समावेशन किया जाना चाहिये।
- हालाँकि पर्यावरण की गुणवत्ता को रातोंरात बहाल करना संभव नहीं है। कति यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हम आगे-पीछे नहीं बल्कि आगे की ओर बढ़ते रहें।

PDF Refernce URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/red-alert-on-the-green-index>

